

“आज के मुख्य समाचार”

- मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का किया आग्रह।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने जंगी-थोपन प्रोजेक्ट पर सरकार को दी राहत- नहीं लौटानी होगी अदानी समूह को 2 सौ 80 करोड़ की प्रीमियम राशि।
- कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सेब पर फैली अल्टरनेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की राज्य सरकार से की मांग।
- केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सीटू ने 4 श्रम संहिताओं को खत्म करने को लेकर प्रदेशभर में किया धरना प्रदर्शन।

भेंट

मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से कल नई दिल्ली में भेंट की। इस दौरान उन्होंने नड्डा को राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधोसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने राज्य के अस्पतालों में स्टेट ऑफ द आर्ट चिकित्सा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर बल देते हुए निर्माणाधीन नाहन, चम्बा और हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालयों का कार्य पूरा करने के लिए धनराशि की मांग की। सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने राज्य में नर्सिंग का प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग देने का भी आग्रह किया ताकि इन्हें विदेशों में भी सेवाएं प्रदान करने के अवसर मिल सकें। मुख्यमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया। जगत प्रकाश नड्डा

ने मुख्यमंत्री को केन्द्र की तरफ से हर संभव सहायता सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।

जंगी थोपन

किन्नौर ज़िले के जंगी थोपन पावर प्रोजैक्ट को लेकर हिमाचल सरकार को प्रदेश उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सिंगल बेंच के फैसले को पलटते हुए न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और विपिन चंद्र नेगी की डिविजन बेंच ने अदानी समूह को 2 सौ 80 करोड़ रूपए की प्रीमियम राशि लौटाने के फैसले को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अदानी समूह इसका हकदार नहीं है और इस समूह ने कोर्ट में विचाराधीन मामले में बैकडोर से प्रोजेक्ट में इनवेस्ट किया जोकि करार के खिलाफ है। इससे पहले इसी प्रोजेक्ट में ब्रेकल कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों पर प्रोजेक्ट हासिल किया था, वो भी करार के खिलाफ पाया गया है ऐसे में ये कम्पनी भी प्रीमियम राशि की हकदार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय—नीट

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी से नीट यूजी-2024 के सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर डालने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उम्मीदवारों के नाम उजागर न करते हुए शहर और केन्द्र-वार परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी लगभग 40 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

शांडिल

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार कृषि में उन्नत तकनीक व अनुसंधान का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। वे आज सोलन ज़िला के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती-खुशहाल

किसान योजना के तहत बिक्री केन्द्र के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र में प्राकृतिक खेती से निर्मित एक सौ से अधिक उत्पाद उपलब्ध होंगे।

जगत नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर ज़िले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर निगुलसरी के समीप बीती रात अवरूद्ध हुए सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क बहाली के कार्य में लगे अधिकारियों व मजदूरों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। जगत सिंह नेगी ने निगुलसरी प्वाइंट से बड़ा-कम्बा स्पैन को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि आपदा के समय किसान व बागवान अपनी नगदी फसलों को मंडियों तक पहुंचा सकें।

इस बीच, जगत सिंह नेगी ने रिकांगपिओ में ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर मॉनसून सीज़न की तैयारियों का जायज़ा लिया और ज़रूरी दिशा-निर्देश दिए। बाद में जनजातीय विकास मंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रिकांगपिओ के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया।

कुलदीप पठानिया

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि विकास व रोज़गार के दृष्टिगत मनरेगा योजना जनहित में कारगर साबित हो रही है। चम्बा ज़िला के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय चुवाड़ी में उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन विकास कार्यों की समीक्षा के बाद प्रधानों, उपप्रधानों और पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि भटियात विकासखण्ड की 20 पंचायतों में मनरेगा के तहत 6 सौ 5 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ 27 लाख से अधिक की राशि आबंटित की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए।

राठौर

कांग्रेस विधायक व राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सेब पर फैली अल्टरनेरिया बीमारी को महामारी घोषित करने की राज्य सरकार से मांग की है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अल्टरनेरिया बीमारी प्रदेश के कई इलाकों में महामारी का रूप धारण कर चुकी है और कुछ इलाकों में 95 फीसदी सेब के बागीचे इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। राठौर ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश सरकार को केन्द्र से बातचीत कर इसकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग ने टीमों प्रभावित इलाकों में भेज दी हैं लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अनुसंधान की ज़रूरत है। उन्होंने विदेशों से आयात हो रहे सेब के पौधों की भी जांच करने की बात कही।

सीटू

केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सीटू ने आज केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू के बैनर तले आंगनबाड़ी, मिड-डे-मील और अन्य कई संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर हल्ला बोला और किसान-मजदूर विरोधी निर्णयों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र मेहरा ने कहा कि जबसे केन्द्र में भाजपा सरकार आई है तब से अमीरों के हित और गरीब मजदूरों के विरोध में फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 4 लेबर कोड लाकर बंधवा मजदूरी की तरफ बढ़ा जा रहा है और मजदूरों के खिलाफ ये काला कानून है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों से सरकार द्वारा कई तरह के काम करवाए जा रहे हैं लेकिन मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। उधर, मण्डी में भी विभिन्न संगठनों से जुड़े सैकड़ों मजदूरों ने रैली निकाली और प्रशासन के माध्यम से

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में केन्द्र द्वारा बनाई गई 4 श्रम संहिताओं को खत्म कर श्रम कानूनों को बहाल करने की मांग की गई है।

अनिरुद्ध सिंह

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज करसोग के चुराग में 4 करोड़ 52 लाख रूपए से बनने वाले खण्ड विकास कार्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने देवता दानवीर कर्ण श्री मूल माहूनाग बखारी कोठी के दो दिवसीय जन्मोत्सव में शिरकत की और पूजा-अर्चना कर देवता का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज विभाग में लगभग 4 हजार पद भरने की प्रक्रिया जारी है।

भाजपा बैठक

प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की विस्तृत व विस्तारित बैठक पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में आज ऊना स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल में हुई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सहप्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव व उपचुनाव जीतने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी गई। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दिनरात मेहनत करने पर उनका आभार व्यक्त किया गया। बिंदल ने कहा कि भाजपा वो पार्टी है जिसने अपना चुनावी सफर 2 सांसदों से शुरू किया था और आज भाजपा ने केन्द्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचा है। बैठक में प्रदेश के सभी भाजपा सांसद व विधायक, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और महामंत्री के अलावा सभी 74 भाजपा मण्डलों के अध्यक्ष व महामंत्री भी मौजूद रहे।

सुंदर ठाकुर

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अधिकारियों के साथ भेंट कर कुल्लू दशहरे के सफल आयोजन को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न देशों के सांस्कृतिक दलों की दशहरे में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श किया।

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने केन्द्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से बल्क ड्रग पार्क के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता का किया आग्रह।
- प्रदेश उच्च न्यायालय ने जंगी-थोपन प्रोजेक्ट पर सरकार को दी राहत- नहीं लौटानी होगी अदानी समूह को 2 सौ 80 करोड़ की प्रीमियम राशि।
- कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने सेब पर फैली अल्टरनेरिया बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की राज्य सरकार से की मांग।
- केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सीटू ने 4 श्रम संहिताओं को खत्म करने को लेकर प्रदेशभर में किया धरना प्रदर्शन।